5

विधि, राजनीति और विचार के संगम का नाम

6

रामजी को पीछे बैठाया, बजरंग दल का विरोध

7

कब होगा "लापरवाही" का विसर्जन

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 22 प्रति सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

कर्ज़ के मायाजाल में फंसी मोहन सरकार, मध्यप्रदेश की जनता पर बढ़ता बोझ

आखिर कब तक कर्ज लेकर रेवड़ियां बांटेगी मोहन सरकार?

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

मध्यप्रदेश की राजनीति में आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर डॉ. मोहन यादव की सरकार किस दिशा में प्रदेश को ले जा रही है। जनता ने जिन सपनों के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी थी, वह क्या अब सिर्फ़ लोन और कर्ज के आंकड़ों में बदलकर रह जाएंगे? हाल ही में सरकार ने एक बार फिर 3 हजार करोड़ रुपये का नया लोन लिया है। यह कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि एक गहरी चिंता का विषय है। इससे पहले सितम्बर 2025 में ही सरकार ने 4500 करोड़ रुपये का भारी-भरकम कर्ज लिया था। यानी कुछ ही महीनों में 7500 करोड़ से अधिक का कर्ज प्रदेश के सिर पर

चढ़ गया। यह संभवतः पहली बार हो रहा है कि किसी भाजपा शासित राज्य की सरकार हर माह लोन लेने की आदत पाल चुकी है। यह स्थिति न केवल वित्तीय अनुशासन पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करती है बल्कि यह भी संकेत देती है कि प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। जब किसी सरकार को बार-बार कर्ज लेना पड़े तो इसका सीधा अर्थ है कि राजस्व संग्रहण और वित्तीय प्रबंधन पूरी तरह विफल हो चुका है।

जनता पर बढ़ता दबाव

हर बार जब सरकार कर्ज लेती है तो अंततः उसका बोझ जनता पर ही पड़ता है। ब्याज का भुगतान जनता की गाढ़ी कमाई से वसूले गए टैक्स से ही होता है। सवाल यह उठता है कि क्या मोहन सरकार प्रदेश की जनता को एक सुनियोजित मायाजाल में फंसा रही है? जहां योजनाओं और विकास के नाम पर लोन लिया जाता है लेकिन असलियत में उसका लाभ जनता को दिखाई नहीं देता। (शेष पेज 2 पर)

छत्तीसगढ़ में जल-जीवन मिशन में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार, आला अधिकारियों की सांठ-गांठ से योजना में लग रहा पलीता

साय सरकार की सख्ती से सुधर रही स्थितियां

-विजया पाठक

केन्द्र सरकार की जल-जीवन मिशन योजना छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। योजना से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी इस महत्वाकांक्षी योजना पर पलीता लगाने पर उतारू हैं। योजना में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के कारण इस योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस योजना के अंतर्गत उपयोग में आने वाली सामग्री की आपूर्ति के लिए अधिकारियों का एक समूह कुछ चुनिंदा कम्पनियों के सीधे संपर्क में है। महकमें की राह कमीशनखोरी की ओर तेजी से बढ़ रही है। एक ओर सिंगल विलीज ठेकेदारों को लम्बे समय से भुगतान नहीं होने से मैदानी इलाकों में योजना ठप्प हो गई है। ग्रामीणों की यह दलील है कि काम पूरा होने के बावजूद ठेकेदारों को राशि नहीं मिलने से अन्य विकास कार्यों में बाधा खड़ी हो गई है। पीड़ित ठेकेदार यह भी तस्दीक कर रहे हैं कि कमीशन की रकम

नहीं देने के चलते "हर घर नल से जल" के प्रमाणन के बावजूद कई तकनीकी और दस्तावेजी आपत्ति लगाकर उच्चाधिकारी भुगतान रोकने के नुस्खें आजमा रहे हैं। राज्यांश राशि वापस लेने के मामले में अफसर भी कोई ठोस वजह नहीं बता पा रहे हैं।

जल जीवन मिशन, केंद्र सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीणों के घरों में नल द्वारा पानी पहुंचाना है।

(शेष पेज 3 पर)

अपराध के साए में मध्यप्रदेश एनसीआरबी की रिपोर्ट में जनजातियों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर चिंताजनक तस्वीर

शांति के टापू मध्यप्रदेश में फैलता जा रहा अपराध और अपराधियों का जाल

-विजया पाठक

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी वर्ष 2023 की अपराध रिपोर्ट ने एक बार फिर मध्यप्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश कई श्रेणियों में शीर्ष स्थानों पर है और दुर्भाग्य से ये स्थान किसी भी राज्य के लिए गौरव नहीं, बल्कि चिंता का विषय हैं। मध्यप्रदेश देश में जनजातीय समुदायों के खिलाफ अपराधों में दूसरे नंबर पर और महिला अपराधों में शीर्ष राज्यों में शामिल है। वहीं, बच्चों के खिलाफ अपराधों में तो प्रदेश ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल कर लिया है। (शेष पेज 3 पर)

मध्यप्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों के पलायन की सबसे बड़ी चुनौती, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने समाधान के खोजे थे कई तरीके

मप्र सरकार को रोजगार के तलाशने होंगे अवसर

-विजया पाठक

त्यौहारी सीजन में जब गाँव और कस्बे रौनक से भर जाने चाहिए, तब मध्यप्रदेश के कई हिस्सों में घर सूने दिखाई देते हैं। कारण है युवाओं और श्रमिकों का पलायन। खासतौर पर आदिवासी और ग्रामीण समाज से जुड़े लाखों लोग रोजगार की तलाश में गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों का रुख करते हैं। यह केवल आर्थिक असुरक्षा का संकेत नहीं, बल्कि प्रदेश के सामाजिक ताने-बाने पर भी गहरी चोट है। मध्यप्रदेश में बेरोजगार युवाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उन्हें रोजगार के अवसर ही नहीं बन रहे हैं। मजबूरी में युवाओं को प्रदेश से बाहर रोजगार के लिए जाना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि प्रदेश में तकनीकि शिक्षा या कौशलवान युवाओं की कमी है। लेकिन जिस स्तर के रोजगार इन्हें मिलना चाहिए वह नहीं मिल

पा रहे हैं। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के युवाओं के बेरोजगारी के समाधान खोजने के प्रयास किये थे। अपने 18 माह के शासनकाल में कमलनाथ ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पहलें शुरू की। कमलनाथ सरकार ने विरासत में मिले खाली खजाने और बदहाल व्यवस्था को सुधारने में अपनी साफ नियत और नीति बनाई। (शेष पेज 2 पर)

मध्यप्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों के पलायन की सबसे बड़ी चुनौती, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने समाधान के खोजे थे कई तरीके

(पेज 1 का शेष)

हर क्षेत्र में उत्पन्न चुनौतियों का सामना करते हुए नई सोच और दृष्टिकोण के साथ काम किया। मध्यप्रदेश के किसानों को राहत पहुँचाई।

रोजगार की दिशा में कमलनाथ ने उठाए थे कदम

रोजगार के लिए कमलनाथ सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे जिनको विजन डाक्यूमेंट में और आगे बढ़ाया गया। कौशल उन्नयन के तहत युवाओं को ट्रेंड कर काम में लगाया गया। मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के तहत भी युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी गई। निवेश के जरिए भी सरकार रोजगार पर फोकस किया था। सरकार ने 70 फीसदी स्थानीय युवाओं को नौकरी देने का नियम भी बनाया। खासतौर पर सरकार ने ग्रामीण रोजगार पर फोकस कर पलायन रोकने की तरफ कदम बढ़ाया। श्रम ब्यूरो के आंकड़ों को देखें तो देश की तुलना में मध्यप्रदेश में बेरोजगारों की संख्या कम थी। यानी यहां के लोगों के हाथों में ज्यादा काम है। श्रम ब्यूरो के मुताबिक देश में 47 फीसदी लोगों के पास काम है जबकि 53 फीसदी बेरोजगार हैं। प्रदेश में 54 फीसदी लोगों के पास रोजगार है जबकि 46 फीसदी बेरोजगार हैं। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कामगारों की संख्या बढ़ी। यानी महिलाओं को ज्यादा रोजगार मिला। इन आंकड़ों से उत्साहित सरकार ने विजन डाक्यूमेंट में ग्रामीण रोजगार पर खास ध्यान दिया था।

रोजगार सृजन कार्यक्रम में प्रदेश आगे: पीएमईजीपी में मध्यप्रदेश ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था। रिपोर्ट में प्रदेश ने पिछले साल के मुकाबले 50 फीसदी ज्यादा रोजगार पैदा किए। साल 2017-18 में 14,432 लोगों को रोजगार मिला था जबकि 2018-19 में ये संख्या बढ़कर 20,208 पर पहुंच गई। साल 2019-20 में अब तक इस योजना के तहत 5552 लोग काम पर लग गए।

ग्रामीण कौशल्या योजना में बढ़ा रोजगार: दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना में मध्यप्रदेश आगे रहा। साल 2017-18 में प्रदेश में इस योजना के तहत 1823 लोगों को रोजगार हासिल हुआ था जबकि 2018-19 में ये संख्या बढ़कर 2098 पर पहुंच गई है।

शहरी आजीविका मिशन में तीन गुना इजाफा: प्रधानमंत्री शहरी आजीविका मिशन के तहत प्रदेश में ट्रेंड वर्कर्स यानी कुशल श्रमिकों की संख्या तीन गुना तक बढ़ी। साल 2017-18 में 3039 लोगों को इस योजना के तहत रोजगार मिला था जबकि 2018-19 में ये संख्या तीन गुना तक बढ़ी। मिशन के तहत प्रदेश सरकार 31,633 लोगों को काम पर लगाया।

पलायन और युवाओं की बेरोजगारी

अगस्त–सितंबर 2025 के हालात बताते हैं कि मध्यप्रदेश से बड़े पैमाने पर युवा अब भी बाहर जा रहे हैं। उद्योग और रोजगार के अवसर सीमित होने के कारण न केवल गरीब तबका, बल्कि शिक्षित युवा भी महानगरों की ओर रुख कर रहे हैं। यह पलायन प्रदेश की ऊर्जा और प्रतिभा को कमजोर करता है। मध्यप्रदेश के लगभग 4 लाख मजदूर दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, जिनमें से लगभग 2 लाख मजदूर दिल्ली में हैं।

कमलनाथ का दृष्टिकोण

कमलनाथ जैसे अनुभवी नेता का योगदान यहाँ महत्वपूर्ण हो सकता था। उनके कार्यकाल में प्रदेश में उद्योग आधारित रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस पहलें शुरू की गई थीं। निवेश आकर्षित करने और स्थानीय स्तर पर छोटे–मझोले उद्योगों (SMEs) को खड़ा करने की योजना उनके विजन का हिस्सा थी। उनका मानना था कि यदि रोजगार के अवसर गाँव और कस्बों तक पहुँचेंगे तो न केवल पलायन रुकेगा, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।

शिक्षा और कौशल विकास

कमलनाथ की सोच हमेशा युवाओं को केंद्र में रखकर रही है। वे मानते थे कि केवल डिग्री से रोजगार संभव नहीं, बल्कि कौशल आधारित शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से ही युवाओं को नए अवसर मिल सकते हैं। आज जब डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे राष्ट्रीय अभियान सक्रिय हैं, तब कमलनाथ जैसे अनुभवी नेतृत्व की भूमिका यह हो सकती थी कि इन योजनाओं को प्रदेश के युवाओं तक वास्तविक रूप से पहुँचाया जाए।

आदिवासी समाज और स्थानीय संसाधन

पलायन की सबसे बड़ी मार आदिवासी समाज पर पड़ रही है। त्यौहार के समय जब उन्हें अपने परिवार और परंपराओं के साथ होना चाहिए, तब वे दूसरे राज्यों में मजदूरी करने को मजबूर हैं। कमलनाथ का दृष्टिकोण यहाँ भी अलग रहा है। वे हमेशा यह मानते रहे कि प्रदेश की प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा को ही रोजगार और विकास का आधार बनाया जाए। वन-उत्पाद, हस्तशिल्प और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर वे आदिवासी समाज को आत्मनिर्भर बनाने का विजन रखते थे। आज जब मध्यप्रदेश युवाओं के पलायन, बेरोजगारी और अवसरों की कमी से जूझ रहा है, तब कमलनाथ जैसे नेता का अनुभव और दृष्टिकोण और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। उनका नेतृत्व यह संदेश देता है कि- यदि उद्योग, शिक्षा और कौशल विकास को स्थानीय स्तर पर जोड़ा जाए तो न केवल पलायन रुकेगा, बल्कि प्रदेश अपने युवाओं की ताकत से आत्मनिर्भर भी बनेगा।

कर्ज़ के मायाजाल में फंसी मोहन सरकार, मध्यप्रदेश की जनता पर बढ़ता बोझ

(पेज 1 का शेष)

आखिर योजनाओं की क्या है सच्चाई?

मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार ने अब तक कोई ऐसी योजना लागू नहीं की है, जिसे मौलिक कहा जा सके। अधिकांश योजनाएँ वही हैं जो शिवराज सिंह चौहान के लंबे कार्यकाल में पहले ही घोषित और प्रारंभ हो चुकी थीं। प्रश्न यह है कि जब नई योजनाएँ शुरू ही नहीं की गईं, तो फिर इतनी बड़ी मात्रा में लोन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या यह धनराशि महज घोषणाओं और प्रचार-प्रसार पर खर्च की जा रही है?

वित्तीय कुप्रबंधन का उदाहरण

एक जिम्मेदार सरकार का काम होता है कि वह संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करे। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। हर महीने नए कर्ज से सिर्फ़ घाटे को ढकने की कोशिश हो रही है। यह स्थिति वैसी ही है जैसे कोई व्यक्ति पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज ले और अंततः पूरी तरह कर्ज के जाल में फंस जाए। मध्यप्रदेश पहले से ही राजस्व संग्रहण में पिछड़ा हुआ राज्य है। औद्योगिक निवेश की कमी, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और बेरोजगारी जैसी चुनौतियाँ पहले से मौजूद हैं। ऐसे में लगातार कर्ज लेना आने वाले वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और कमजोर कर देगा। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाली पीढ़ियाँ भी इस बोझ से मुक्त नहीं हो पाएंगी।

जनता के साथ मोहन सरकार का धोखा

चुनाव से पहले जो वादे किए गए थे, उनमें विकास, रोजगार, किसानों की समृद्धि और युवाओं को अवसर देने की बातें शामिल थीं। लेकिन अब तक जो परिदृश्य सामने आया है, उसमें सिर्फ़ कर्ज की कहानी है। जनता यह पूछने के लिए विवश है कि आखिर उसकी मेहनत की कमाई किस दिशा में खर्च हो रही है। क्या यह जनता के साथ एक बड़ा धोखा नहीं है? मोहन सरकार ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया कि लिए गए कर्ज का उपयोग किन योजनाओं के लिए हो रहा है। न कोई सार्वजनिक विवरण, न ही कोई पारदर्शी रिपोर्ट जनता के सामने रखी गई। यदि सब कुछ विकास और कल्याणकारी योजनाओं में जा रहा है तो इसमें छुपाने जैसा क्या है? जवाबदेही से बचने की यह कोशिश सरकार की नीयत पर सवाल उठाती है। राजनीति में बने रहने और जनता के बीच छवि गढ़ने के लिए सरकारें अक्सर दिखावटी कदम उठाती हैं। कहीं यह कर्ज लेना भी उसी महत्वाकांक्षा का हिस्सा तो नहीं? योजनाओं के नाम पर घोषणाएँ, कार्यक्रमों के नाम पर खर्च और असल मुद्दों को दरकिनार करना- यह सब एक गंभीर लक्षण है कि सरकार विकास की बजाय केवल राजनीतिक अस्तित्व बचाने में लगी हुई है।

मध्यप्रदेश का भविष्य खतरे में

यदि यही क्रम चलता रहा तो कुछ ही वर्षों में मध्यप्रदेश की स्थिति वैसी हो सकती है जैसी कभी ग्रीस जैसे देशों की हो गई थी- जहाँ हर ओर सिर्फ़ कर्ज और दिवालियापन की बातें होती हैं। प्रदेश की आम जनता पहले ही महंगाई, बेरोजगारी और मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रही है। ऐसे में कर्ज का बोझ उसे और अधिक दबा देगा। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि डॉ. मोहन यादव की सरकार किस दिशा में जा रही है? क्या यह सरकार केवल कर्ज लेकर प्रदेश को भविष्य के संकट की ओर धकेल रही है, या फिर वास्तव में कोई ठोस विकास का खाका तैयार है? जब तक सरकार जनता को स्पष्ट जवाब नहीं देती, तब तक यह मानना ही पड़ेगा कि यह कर्ज का मायाजाल केवल जनता को दबाने और वास्तविक समस्याओं से ध्यान हटाने का प्रयास है। प्रदेश की जनता अब केवल वादों और नारों से संतुष्ट नहीं होगी। उसे चाहिए पारदर्शिता, जवाबदेही और ठोस विकास। यदि मोहन सरकार ने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो इतिहास उसे केवल एक ऐसी सरकार के रूप में याद रखेगा जिसने प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबा दिया।

छत्तीसगढ़ में जल-जीवन मिशन में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार

(पेज 1 का शेष)

छत्तीसगढ़ में इस मिशन के तहत अब तक 40 लाख से अधिक परिवारों को नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस राज में पटरी से उतरी जल-जीवन मिशन की नैय्या बीजेपी शासनकाल में भी भ्रष्टाचार की गहरी खाई में गोता लगाते नजर आ रही है। पीड़ितों के मुताबिक भूपेश राज में बिल भुगतान का कमीशन 07 फ़ीसदी पर स्थिर था, जो मौजूदा शासनकाल में 10 फीसदी का आंकड़ा पार करने के मिशन पर अग्रसर है। उनके मुताबिक राज्य की साय सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए गाँव–कस्बों में कार्यरत सैकड़ों छोटे ठेकेदारों की सुध लेते हुए उनका भुगतान सुनिश्चित करने हेतु बजट आवंटित कर दिया था। लेकिन अफसरों की प्रभावशील टोली ने सिंगल विलेज ठेकेदारों के हिस्से की रकम मल्टी विलेज ठेकेदारों की तिजोरी में डाल दी। ऐसे मल्टी विलेज ठेकेदारों की संख्या सिर्फ आधा दर्जन बताई जाती है, जबकि सिंगल विलेज ठेकेदार महज कुछ सैकड़ा ही है। जल-जीवन मिशन की कामयाबी इन्हीं सिंगल विलेज ठेकेदारों के कामकाज पर निर्भर बताई जाती है। यह भी तस्दीक की जा रही है कि मैदानी इलाकों में कार्यरत छोटे ठेकेदारों का भुगतान नहीं होने से इस महती योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में आज भी कठिनाई का दौर जस की तस है। जल जीवन मिशन में लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार के ग्राफ से राज्य की बीजेपी सरकार की साख भी दांव पर बताई जाती है।

रायपुर में जल जीवन मिशन के मुख्यालय में सिंगल विलेज ठेकेदारों का ताँता लगा हुआ है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से कई ठेकेदार अपने लंबित भुगतान को लेकर डेरा डाले हुए हैं। उन्हें उस समय निराशा हाथ लग रही है, जब पता पड़ रहा है कि इस योजना अंतर्गत आवंटित राज्यांश की रकम अचानक वापस लेने का फरमान जारी हो गया है। दावा किया जा रहा है कि मोटा कमीशन का अग्रिम भुगतान

वसूलने के बाद उनके हिस्से की रकम चुनिंदा मल्टीविलेज एजेंसियों को भुगतान के लिए परिवर्तित कर दी गई है। इस रकम को एडिशनल एमडी एसएन पांडेय की क़वायतों के कारण डिवीजनल कार्यालयों से वापस ले लिया गया है। यही नहीं जिला कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों को कमीशन का टारगेट भी सौंपा गया है। इसकी भरपाई न करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों को ट्रांसफर करने की धमकी भी दी जा रही है।

कनिष्ठ अधिकारियों के भरोसे योजना

शिकायतकर्ताओं के मुताबिक एडिशनल MD का पद ENC स्तर के अधिकारियों के लिए पूर्व निर्धारित है, लेकिन मौजूदा दौर में "कमीशनखोरी" को यथावत जारी रखने के लिए "E" अर्थात इंजिनियर के पद पर काबिज कनिष्ठ अधिकारी को इतने महत्वपूर्ण और जिम्मेदार पद की कुर्सी पर बैठा दिया गया है। इस अफसर की कार्यप्रणाली को लेकर महकमें में कोहराम मचा है। पीड़ितों के मुताबिक विभागीय बैठकों में खुलकर कमीशन माँगा जा रहा है, अन्यथा अधिकारियों को ट्रांसफर करने की धमकी भी दी जा रही है। पीड़ित तस्दीक करते हैं कि एडिशनल MD की कार्यप्रणाली उच्च स्तरीय जाँच के दायरे में है, लेकिन राजनैतिक संरक्षण के चलते उपकृत करने का सिलसिला जारी है। सूत्रों के मुताबिक राज्य को योजना में अपेक्षित विकास कार्य नहीं होने के चलते केन्द्रांश स्वीकृत नहीं हो रहा है। हालांकि कुछ माह पहले ही लगभग 371 करोड़ का राज्यांश के रूप में धनराशि सीधे तौर पर जिलों को आवंटित की गई थी। लेकिन प्रीपेड कमीशन के चलते अधिकारियों ने प्रभावशाली और चहेती एजेंसियों का भुगतान सुनिश्चित कर दिया। उसने विभिन्न जिलों को आवंटित राशि भी वापस लेने का फरमान जारी कर विभागीय गतिरोध पैदा कर दिया। बताया जाता है कि सभी खंड कार्यालयों से यह आवंटित राशि वापस ली जा रही है। पीड़ितों के मुताबिक रायपुर, सारंगढ़ बिलाईगढ़, गरियाबंद, धमतरी, बेमेतरा, महासमुंद समेत कई जिलों से यह राशि वापस हो गई है।

ठेकेदारों से लेकर आलाधिकारियों की पौ बारह

छत्तीसगढ़ में जल-जीवन मिशन योजना से आम आबादी को पानी अभी नहीं मिल पाया है। लेकिन योजना में भ्रष्टाचार से ठेकेदारों से लेकर आलाधिकारियों की पौ बारह है। इस योजना से बड़े पैमाने पर ब्लैकमनी के उत्पादन की बू आ रही है। इसकी बंदरबांट को लेकर कई जिलों में ठेकेदारों की हड़ताल के बावजूद अफसरों की कार्यप्रणाली पर कोई असर नहीं पड़ा है। उनकी कार्यप्रणाली जस की तस होने से सरकारी तिजोरी पर सेंधमारी जोरों पर है। ऐसे अफसरों से त्रस्त कई ठेकेदारों ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को अवगत कराया है। इस योजना के जरिए तैयार ब्लैकमनी के स्रोतों की जानकारी आयकर-ईडी और सीबीआई को भेजी गई है। दरअसल, जल-जीवन मिशन योजना का वित्तीय भार आधा केंद्र और आधा छत्तीसगढ़ शासन वहन कर रहा है।

अपराध के साए में मध्यप्रदेश एनसीआरबी की रिपोर्ट में जनजातियों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर चिंताजनक तस्वीर

(पेज 1 का शेष)

यह स्थिति बताती है कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग महिलाएं, बच्चे और जनजातीय समुदाय आज भी सुरक्षा और न्याय की उम्मीद में असुरक्षा के घेरे में जी रहे हैं।

महिलाओं और बच्चों पर अपराध भयावह

एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि मध्यप्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। दुष्कर्म के मामलों में राज्य देश में तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2023 में 2,979 दुष्कर्म के प्रकरण दर्ज किए गए। तुलना करें तो राजस्थान में 5,078 और उत्तर प्रदेश में 3,516 घटनाएं दर्ज हुईं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश में अब भी ठोस सुधार की आवश्यकता है। महिलाओं पर हिंसा, दहेज हत्या, उत्पीड़न और शारीरिक शोषण जैसे अपराधों में भी गिरावट के कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिखते। वर्ष 2023 में दहेज हत्या के 468 मामले दर्ज किए गए, जबकि घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के प्रकरण हजारों की संख्या में सामने आए। जहाँ एक ओर सरकार "नारी सशक्तिकरण" की बात करती है, वहीं दूसरी ओर ये आंकड़े उस दावे की जमीनी हकीकत को उजागर करते हैं।

मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग, फिर भी नहीं थम रहे अपराध

मध्यप्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। राज्य के गृहमंत्री स्वयं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हैं, बावजूद इसके आपराधिक घटनाओं में अपेक्षित कमी नहीं आ रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) की वर्ष 2023 की रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश महिलाओं, बच्चों और जनजातीय समुदायों के खिलाफ अपराधों में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। महिला अपराधों में मध्यप्रदेश तीसरे स्थान पर है, वहीं बच्चों के खिलाफ अपराधों में प्रदेश देश में पहले नंबर पर पहुंच गया है। दुष्कर्म, अपहरण, बाल उत्पीड़न और घरेलू हिंसा जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कानून-व्यवस्था की सख्ती के दावों के बावजूद अपराधियों में पुलिस या प्रशासन का भय नजर नहीं आता। विशेषज्ञों का मानना है कि अपराध नियंत्रण के लिए केवल सख्त कानून पर्याप्त नहीं, बल्कि उनकी कड़ाई से क्रियान्वयन, जवाबदेह पुलिस व्यवस्था और तेज न्याय प्रक्रिया की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब प्रदेश में कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण और आमजन में सुरक्षा का विश्वास बहाल करने की है। अगर तत्काल प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो "शांत प्रदेश" की पहचान अपराधों के साए में खोती जा सकती है।

बच्चों के खिलाफ अपराध अव्वल मध्यप्रदेश

सबसे चिंताजनक स्थिति बच्चों के खिलाफ अपराधों की है। एनसीआरबी के अनुसार वर्ष 2023 में मध्यप्रदेश में 1.77 लाख से अधिक प्रकरण बच्चों के खिलाफ दर्ज किए गए। यह आंकड़ा पिछले वर्ष (2022) की तुलना में 9 प्रतिशत अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार, हर दिन औसतन 486 और हर तीन मिनट में एक अपराध बच्चों के खिलाफ दर्ज किया गया। यह स्थिति न केवल कानून-व्यवस्था की कमजोरी का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि समाज की मानसिकता और संरचना में गहरा संकट मौजूद है। यौन उत्पीड़न, अपहरण, बाल विवाह, बाल मजदूरी और विद्यालयी उत्पीड़न जैसे अपराध बच्चों की सुरक्षा को लेकर भयावह स्थिति को उजागर करते हैं। मध्यप्रदेश में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए कानून और संस्थाएँ कागजी साबित हो रही हैं।

संवेदनशील समुदायों पर बढ़ते हमले

एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ 2,858 अपराध दर्ज किए गए। यह संख्या वर्ष 2022 के 2,979 मामलों से थोड़ी कम है, लेकिन देश के बड़े राज्यों में मध्यप्रदेश अब भी पहले स्थान पर है। हालाँकि, देशभर के राज्यों को मिलाकर देखें तो मणिपुर में आदिवासियों के खिलाफ सबसे अधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। बावजूद इसके, मध्यप्रदेश की स्थिति बेहद संवेदनशील मानी जा रही है। यह तथ्य चिंताजनक है कि जिन जनजातीय समुदायों को संविधान ने विशेष संरक्षण दिया है, वे आज भी हिंसा, उत्पीड़न और शोषण के शिकार बन रहे हैं। विशेष रूप से बालाघाट, मंडला, झाबुआ और अलीराजपुर जैसे आदिवासी बहुल जिलों से अधिक मामले सामने आए हैं।

हत्या और अपहरण के मामलों में मामूली सुधार, फिर भी स्थिति गंभीर

हत्या के मामलों में वर्ष 2023 में कुछ कमी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 1,832 हत्याएं हुईं, जबकि वर्ष 2022 में यह संख्या 1,978 और 2021 में 2,034 थी। यह गिरावट राहत जरूर देती है, परंतु समग्र परिप्रेक्ष्य में आंकड़े अब भी भयावह हैं। अपहरण के मामलों में स्थिति उलट है यहां वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2023 में 11,768 अपहरण की घटनाएं दर्ज हुईं, जिससे मध्यप्रदेश इस श्रेणी में देश का पांचवां सबसे अधिक अपराध वाला राज्य बन गया। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के बाद अब मध्यप्रदेश भी इस सूची में प्रमुखता से शामिल हो चुका है।

आत्महत्याएँ और सामाजिक तनाव

एनसीआरबी के अनुसार, मध्यप्रदेश में आत्महत्या के मामलों में भी गंभीर स्थिति बनी हुई है। वर्ष 2023 में 15,662 लोगों ने आत्महत्या की, जिससे राज्य देश में तीसरे स्थान पर है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक असुरक्षा और सामाजिक दबाव जैसे कारण लोगों को चरम कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बेरोजगारी, पारिवारिक कलह, आर्थिक संकट और असफलता का भय आत्महत्या के बढ़ते मामलों के प्रमुख कारण हैं।

अपराध की जड़ें और प्रशासनिक चुनौतियाँ

मध्यप्रदेश की सामाजिक बनावट विविध है यहाँ आदिवासी, ग्रामीण, शहरी और औद्योगिक क्षेत्र समान रूप से मौजूद हैं। लेकिन अपराध की प्रकृति बताती है कि आर्थिक असमानता, शिक्षा की कमी, बेरोजगारी और सामाजिक असंतुलन इसके मूल कारण हैं। राज्य में महिला और बाल सुरक्षा से जुड़े कानून जैसे पॉक्सो अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम तो हैं, परंतु उनका प्रभावी क्रियान्वयन अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। पुलिस बलों पर कार्यभार का दबाव, अनुसंधान की धीमी प्रक्रिया, और पीड़ितों की शिकायतों पर संवेदनशीलता की कमी भी अपराध नियंत्रण में बड़ी बाधा है।

सरकार के लिए चेतावनी की घंटी

इन आंकड़ों ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अपराधों में लगातार बढ़ोतरी बताती है कि केवल घोषणाएँ और योजनाएँ पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर संवेदनशील, जवाबदेह और प्रभावी तंत्र की जरूरत है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर जिला प्रशासन तक सभी को ठोस कदम उठाने होंगे। समाज में जागरूकता अभियान, त्वरित न्याय प्रणाली, और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई को प्राथमिकता देनी होगी।

सुधार की राह अब भी लंबी

एनसीआरबी की रिपोर्ट केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि एक आईना है जो बताता है कि मध्यप्रदेश को अपनी सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में गहरे सुधार की आवश्यकता है। जहाँ कुछ अपराधों में मामूली गिरावट राहत देती है, वहीं अधिकांश श्रेणियों में प्रदेश का शीर्ष पर होना चिंता का विषय है। जनजातियों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की यह भयावह स्थिति बताती है कि विकास की दौड़ में कहीं न कहीं मानवीय सुरक्षा और संवेदनशीलता पीछे छूट रही है। मध्यप्रदेश को अब केवल अपराध नियंत्रण नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार, न्यायिक तत्परता और प्रशासनिक जवाबदेही की नई परिभाषा गढ़नी होगी। तभी यह कहा जा सकेगा कि प्रदेश सचमुच "दिल से बड़ा" है न कि अपराधों से।

सम्पादकीय

संघ शताब्दी वर्ष और भारत राष्ट्र का एकत्व

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का शताब्दी वर्ष केवल किसी संगठन का उत्सव नहीं है, बल्कि यह भारत राष्ट्र की आत्मा, संस्कृति और एकत्व की पुनर्पुष्टि का अवसर है। 1925 में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा स्थापित संघ ने अपनी सौ वर्ष की यात्रा में यह सिद्ध किया है कि संगठन शक्ति ही राष्ट्र निर्माण की वास्तविक आधारशिला है। संघ का शताब्दी पर्व इस सत्य को पुनः रेखांकित करता है कि भारत का एकत्व उसकी विविधता में निहित है, और यह विविधता तभी टिकाऊ है जब समाज में संगठन, समरसता और सांस्कृतिक चेतना का प्रवाह सतत बना रहे। 20वीं शताब्दी का आरंभ भारत के लिए राजनीतिक उथल-पुथल का दौर था। स्वतंत्रता की आकांक्षा तो प्रबल थी, परंतु समाज जाति, प्रांत और संप्रदायों में बंटा हुआ था। ऐसे समय में संघ ने सामाजिक संगठन की आवश्यकता को पहचाना। शाखा के माध्यम से अनुशासन, शारीरिक एवं मानसिक विकास और राष्ट्रनिष्ठा का संस्कार पीढ़ियों में बोया गया। यही बीज आज वटवृक्ष बनकर भारतीय समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी छाया फैला रहा है।

शताब्दी पर्व केवल गौरव का स्मरण नहीं है, यह नव संकल्प का समय है। आज भारत विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। तकनीक, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। परंतु इन उपलब्धियों के बीच सांस्कृतिक एकता और समाज जीवन में समरसता को बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। संघ का शताब्दी वर्ष इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें स्मरण कराता है कि राष्ट्र की शक्ति केवल आर्थिक और राजनीतिक सामर्थ्य से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना और संगठन से आती है।

भारत की पहचान उसकी अनेकता में एकता है। हिमालय से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक, भाषा, खान-पान, वेशभूषा और परंपराओं की असंख्य विविधताएँ हैं। फिर भी हर भारतीय की आत्मा में एक ही भाव गूंजता है– भारत माता। संघ ने हमेशा इस भाव को जीवित रखने के लिए कार्य किया। 'एकात्म मानव दर्शन' और 'समरसता' के सिद्धांत संघ के विचार की धुरी हैं। एकत्व का अर्थ केवल भौगोलिक अखंडता नहीं है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकात्मता है। जाति-भेद, छुआछूत, प्रांतवाद और संप्रदायवाद जैसे विभाजनकारी तत्वों को समाप्त कर समाज में 'हम सब एक हैं' का भाव जागृत करना ही वास्तविक राष्ट्र निर्माण है।

संघ ने शताब्दी की इस यात्रा में सेवा कार्यों को अपना प्रमुख माध्यम बनाया। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में लाखों स्वयंसेवक निरंतर सक्रिय हैं। सेवा भारती, विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्थाएँ इसी संगठनात्मक शक्ति की उपज हैं। पद संचलन, शाखाएँ और प्रशिक्षण शिविर केवल अनुशासन का अभ्यास नहीं, बल्कि यह समाज जीवन में संगठन की जीवंत झलक हैं। ये हमें बताते हैं कि जब तक समाज संगठित नहीं होगा, तब तक राष्ट्र की शक्ति अधूरी रहेगी।

भारत आज विश्व के सामने तेजी से प्रगति करता हुआ देश है। परंतु वैश्विकरण, सांस्कृतिक विघटन, उपभोक्तावाद और राजनीतिक असंतुलन जैसी चुनौतियाँ भी हमारे सामने हैं। इन परिस्थितियों में संघ का शताब्दी वर्ष हमें मार्गदर्शन देता है कि हम आधुनिकता को आत्मसात करें, परंतु अपनी सांस्कृतिक जड़ों से न कटें। भारतीय संस्कृति हमें वसुधैव कुटुंबकम् का संदेश देती है। यही भाव भारत को विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ाता है। संघ की शिक्षा यह है कि यदि समाज संगठित है तो कोई भी शक्ति हमें विभाजित नहीं कर सकती। शताब्दी वर्ष में प्रवेश करते हुए स्वयंसेवकों और समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए यह अवसर है कि वे संघ के मूल मंत्रों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं– अनुशासन, सेवा, संगठन और राष्ट्रभक्ति। आने वाले वर्षों में भारत केवल आर्थिक महाशक्ति ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक शक्ति के रूप में भी दुनिया का मार्गदर्शन करेगा। संघ शताब्दी वर्ष और भारत राष्ट्र का एकत्व– यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि भारतीय समाज की सामूहिक आकांक्षा है। जब समाज जाति, वर्ग, प्रांत और संप्रदाय से ऊपर उठकर एकात्मता के भाव से कार्य करेगा, तब भारत सशक्त, आत्मनिर्भर और विश्व के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा। संघ की शताब्दी इस यात्रा का स्मरण कराते हुए हमें यह संकल्प दिलाती है कि आने वाला शताब्दी काल नवजागरण और राष्ट्रनिर्माण का कालखंड होगा।

सियासी गहमागहमी

शिवराज सिंह चौहान का भोपाल प्रेम नहीं हो रहा कम

लगता है शिवराज सिंह चौहान का दिल भोपाल से ऐसे जुड़ गया है जैसे मछली का पानी से। सत्ता हो या विपक्ष, मुख्यमंत्री की कुर्सी हो या पूर्व मुख्यमंत्री का ठप्पा, उनका भोपाल प्रेम किसी भी मौसम में कम नहीं होता। विधानसभा का सेशन हो या जम्बूरी मैदान की रैली, स्मार्ट सिटी का सपना हो या झील के किनारे टहलना- हर जगह शिवराज की उपस्थिति भोपालियों के लिए "सदैव उपलब्ध" रहती है। कभी वे कहते हैं कि भोपाल उनका दिल का टुकड़ा है, तो कभी झीलों की नगरी को अपना घर बताकर भावुक हो जाते हैं। अब जनता सोचती है कि अगर इतना ही मोह है, तो क्यों न भोपाल को ही स्थायी मुख्यमंत्री निवास घोषित कर दिया जाए! शहर की सड़कों से लेकर फ्लाईओवर और उद्यानों तक, सब जगह उनका नाम गूंजता है। लगता है जैसे भोपाल उनकी राजनीतिक यात्रा का "चार्जिंग स्टेशन" हो, जहाँ से ऊर्जा लेकर वे पूरे प्रदेश में अभियान छेड़ते हैं।

कांग्रेस में कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी देने पर विचार

कांग्रेस पार्टी की आदत बड़ी निराली है। जब भी संगठन लड़खड़ाता है या चुनावी बैसाखी टूटने लगती है, तब नेताओं की पुरानी अलमारी खोलकर "अनुभव की पोटली" ढूंढी जाती है। इस बार चर्चा है कि कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी देने पर विचार चल रहा है। कमलनाथ जी तो वैसे भी राजनीति के एवरग्रीन पौधे हैं- न मौसम से सूखते, न परिस्थिति से झुकते। मुख्यमंत्री पद खोने के बाद भी उनकी सक्रियता में कोई कमी नहीं आई, बल्कि अब वे खुद को कांग्रेस के संजीवनी बूटी वाले हनुमान साबित करने पर तुले हैं। कांग्रेस हर संकट में उन्हीं चेहरों पर भरोसा करती है जिनसे संकट पैदा हुआ हो या कम से कम जिनकी उम्र अब आराम की कुर्सी पर बैठने की हो। नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देने का नारा बस भाषणों में ही रहता है, बाकी तो वही "पुराने घोड़े" मैदान में उतारे जाते हैं। अब सवाल यह है कि कांग्रेस की यह रणनीति पार्टी को संजीवनी देगी या फिर यह "अंतिम भरोसा" साबित होगी। जनता तो बस इतना कह रही है- अगर बड़ी जिम्मेदारी देना ही है तो साथ में "जीत की गारंटी कार्ड" भी दे दीजिए, वरना नाथ जी का अनुभव भी चुनावी मशीन की बैटरी चार्ज नहीं कर पाएगा।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

भोपाल, मध्यप्रदेश में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई दुर्घटनाओं में कई लोगों की मृत्यु, जिनमें अधिकतर बच्चे हैं, अत्यंत हृदयविदारक है।

इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों और बच्चों के अभिभावकों के साथ हैं। हादसों में घायल लोगों की कुशलता और जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

जहरीला कफ सिरप पीने से अब तक छिंदवाड़ा में 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। दुख की इस घड़ी में मेरी भावनाएँ पीड़ित परिवारों के साथ हैं। लेकिन यह याद रखना होगा कि यह महज दुर्घटना नहीं बल्कि मानव निर्मित त्रासदी है। मैं मध्य प्रदेश सरकार से माँग करता हूँ कि एक-एक मृत बच्चे के परिजनों को 50-50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

डॉ. कपिल सिब्बल विधि, राजनीति और विचार के संगम का नाम

समता पाठक/जगत प्रवाह

भारतीय राजनीति और विधि के क्षेत्र में डॉ. कपिल सिब्बल का नाम एक ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के रूप में लिया जाता है, जिन्होंने कानून, शिक्षा, प्रशासन और सार्वजनिक जीवन में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। वे न केवल एक प्रख्यात वकील हैं, बल्कि एक कुशल प्रशासक, विचारवान नेता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रबल समर्थक के रूप में भी जाने जाते हैं। उनका जीवन संघर्ष, अध्ययन और आत्मविश्वास की उस प्रेरक यात्रा का प्रतीक है, जिसने उन्हें भारतीय सार्वजनिक जीवन के उच्चतम शिखर तक पहुँचाया। कपिल सिब्बल का जन्म 8 अगस्त 1948 को पंजाब के जालंधर में हुआ। उनके पिता एच.एल. सिब्बल देश के जाने-माने विधिवेत्ता थे, जिन्होंने उन्हें बचपन से ही न्याय और नैतिकता के मूल्य सिखाए। प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में पूरी करने के बाद उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि (LL.B) की पढ़ाई की और फिर हार्वर्ड लॉ स्कूल (अमेरिका) से मास्टर ऑफ लॉ (LL.M) की उपाधि अर्जित की। यह शिक्षा केवल एक शैक्षणिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि उनके व्यक्तित्व को अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदान करने वाला अनुभव था। यहीं से उन्होंने समझा कि कानून केवल नियमों का संग्रह नहीं, बल्कि समाज की आत्मा को संचालित करने वाला तत्व है। भारत लौटने के बाद कपिल सिब्बल ने 1970 के दशक में वकालत की शुरुआत की। वे शीघ्र ही देश के शीर्ष वकीलों में गिने जाने लगे। 1983 में उन्हें भारत सरकार का वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किया गया। उन्होंने अनेक संवैधानिक, राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में अपनी प्रभावशाली पैरवी से ख्याति अर्जित की। उनकी कानूनी दृष्टि, तार्किक विवेचना और प्रखर वक्तृत्व शैली ने उन्हें न्यायिक जगत में एक अलग पहचान दी। उन्होंने कई ऐतिहासिक मामलों में सरकारों, संस्थाओं और नागरिकों का पक्ष रखा और संवैधानिक मर्यादाओं की रक्षा की।

कपिल सिब्बल की राजनीतिक यात्रा 1990 के दशक की शुरुआत में कांग्रेस पार्टी से जुड़ने के साथ शुरू हुई। 1998 में वे पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने। इसके बाद वे लगातार राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहे और 2004 तथा 2009 में दिल्ली से लोकसभा सांसद चुने गए। उनके राजनीतिक करियर की विशेषता यह रही कि उन्होंने केवल राजनीति को सत्ता का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि उसे सुधार और नीति-निर्माण का उपकरण बनाया। उन्होंने संचार, विज्ञान, शिक्षा, कानून और मानव संसाधन जैसे जटिल मंत्रालयों का सफलतापूर्वक संचालन किया। मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में कपिल सिब्बल ने शिक्षा व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में ग्रेडिंग प्रणाली लागू की, जिससे बच्चों पर परीक्षा का दबाव कम हुआ। उन्होंने शिक्षा में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया और "आकाश टैबलेट" जैसी पहलें शुरू कीं ताकि ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों तक डिजिटल शिक्षा पहुंच सके। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री के रूप में उन्होंने अनुसंधान और नवाचार को नई दिशा दी। उनकी सोच थी कि भारत की प्रगति विज्ञान और ज्ञान के विस्तार में निहित है।

संचार मंत्री के रूप में कपिल सिब्बल को 2G स्पेक्ट्रम विवाद जैसे कठिन दौर से गुजरना पड़ा। उन्होंने सदैव यह दावा किया कि उनकी प्राथमिकता नीति-निर्माण में पारदर्शिता और जवाबदेही को स्थापित करना है। उन्होंने कहा था कि "नीतियाँ समय के साथ बदलनी चाहिए, परंतु सिद्धांत वही रहना चाहिए- जनहित सर्वोपरि।" कपिल सिब्बल न केवल एक राजनीतिज्ञ और वकील हैं, बल्कि एक संवेदनशील लेखक और कवि भी हैं। उन्होंने कई कविताएँ और लेख लिखे, जिनमें लोकतंत्र, प्रेम, समाज और न्याय जैसे विषयों की गहराई झलकती है। उनकी रचनाएँ इस बात का प्रमाण हैं कि वे केवल कानून के जानकार नहीं, बल्कि विचार के साधक भी हैं। वह भारतीय लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सशक्त समर्थक रहे हैं। संसद में उनके भाषण सदैव तर्क, संवेदना और विवेक का संतुलन प्रस्तुत करते हैं। कांग्रेस से लंबे समय तक जुड़े रहने के बाद, 2022 में कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ दी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राज्यसभा पहुंचे, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया। यह कदम उनके स्वतंत्र राजनीतिक दृष्टिकोण और आत्मनिर्भर विचारधारा का प्रतीक था। उन्होंने कहा था कि "राजनीति में व्यक्ति नहीं, विचार महत्वपूर्ण होते हैं। डॉ. कपिल सिब्बल का जीवन भारतीय लोकतंत्र के उस आदर्श का प्रतीक है जिसमें ज्ञान, अनुभव, निष्ठा और विवेक का अद्भुत संगम है। वे उन विरले नेताओं में हैं जिन्होंने राजनीति को बौद्धिकता के स्तर पर जिया है। उन्होंने बार-बार यह सिद्ध किया कि सच्चा जनसेवक वह है जो सत्ता की भीड़ में भी विवेक की आवाज बन सके।

विजयदशमी पर दशहरा मैदान में गूंजे देवी भोले और श्रीराम के भजन, झूम उठे श्रद्धालु

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। विजयदशमी पर दशहरा मैदान में रावण दहन के बाद भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर की संगीत संस्था म्यूजिक जोन ने शानदार भजनों की प्रस्तुति दी। विजयदशमी पर रामलीला महोत्सव समिति द्वारा आयोजित भजन संध्या का भजन प्रेमियों ने खूब आनंद उठाया और झूम उठे।

कार्यक्रम का शुभारंभ रामलीला महोत्सव समिति के अध्यक्ष पंडित गिरजा शंकर शर्मा और म्यूजिक जोन के संरक्षक राकेश पौजदार, डॉ. वैभव शर्मा, रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष और रामलीला प्रमुख पंडित अरुण शर्मा, सचिव ज्ञानेश्वर तिवारी, संगीतज्ञ राम परसाई ने माता दरबार में दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर आरती के साथ किया। मां की आरती म्यूजिक जोन के पंडित सुनील मिश्रा द्वारा प्रस्तुत की गई। सुनील मिश्रा द्वारा गाए भजन मारे कीर्तन में रस बरसाओ से किया गया। मां के दरबार में म्यूजिक जोन के अध्यक्ष और ख्याति प्राप्त गायक असीम विश्वास द्वारा तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मुकेश गढ़वाल के साथ प्रस्तुत किया गया। म्यूजिक जोन के प्रतीक द्विवेदी ने हे कालरात्रि मां कल्याणी और मां शेरावालिए। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे मशहूर भजनों को अपनी आवाज दी। वैभव शुक्ला ने हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ सौम्या कौशिक के साथ गाकर खूब तालिया बटोरी। संयम बिल्लौरे डूब चलो दिन अभिलाष दुबे ने बंसी वाले को तुम याद कर लो। मुकेश गढ़वाल ने असीम विश्वास के साथ चलो बुलावा आया है। वैभव शुक्ला और प्रतीक द्विवेदी का गाया देखा हो श्री गणेशा भजन खूब सराहा गया। म्यूजिक जोन के कलाकार अजय बरखने, गंगाराम सोनिया, कुमारी साधना मेहरा और अजय दुबे, आनंद शुक्ला ने भक्ति भजनों पर दर्शकों के साथ मिलकर खूब नाचे खूब झूमे जिससे वातावरण एकदम भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम का सफल संचालन म्यूजिक के सचिव सईद कुरैशी द्वारा किया गया।

छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र में हो रहा विकासः मुख्यमंत्री साय

भंडारपुरी धाम में आयोजित गुरु दर्शन एवं संत समागम मेला में हुए शामिल

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। प्रदेश के हर क्षेत्र का विकास तेजी से हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता से जो भी वादे किए थे, उन्हें हम 'मोदी की गारंटी' के रूप में पूरा कर रहे हैं। अब तक नौ हजार से अधिक सरकारी भर्तियाँ पूरी हो चुकी हैं और हाल ही में शिक्षा विभाग में पाँच हजार पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि शासन के प्रत्येक कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए संकल्पित है। भ्रष्टाचार करने वाला चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर जिले के आरंग तहसील अंतर्गत भंडारपुरी धाम में आयोजित गुरु दर्शन एवं संत समागम मेला में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर कही। इस अवसर पर उन्होंने 162 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 16 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया, जिनमें नवीन सड़क निर्माण, चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री

साय ने मेला स्थल पर डोम निर्माण, तेलासी-भंडारपुरी मार्ग में स्ट्रीट लाइट लगवाने तथा कुटेसर प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यदि समाज से पाँच युवा पायलट बनना चाहें तो उनका पूरा खर्च सरकार वहन करेगी और उन्हें पायलट बनाया जाएगा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बाबा गुरु घासीदास के आदर्शों पर चलकर हमें विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। उनके आदर्शों में मानवता और समानता की सीख निहित है। गुरु बाबा ने समाज को एकजुट होने का संदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप सतनामी समाज आज प्रगति और सौहार्द की दिशा में अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि पिछले वर्ष भी मुझे मुख्यमंत्री के रूप में इस मेले में शामिल होने का अवसर मिला। लेकिन इस वर्ष और पिछले वर्ष में बड़ा अंतर आया है। पिछले वर्ष जब मैं यहां आया था तब आपके समाज के गुरु श्री खुशवंत साहेब विधायक थे, अब वे मंत्री बने हैं। उन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास तथा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आपके समाज के गौरव से हमें अपार उम्मीदें हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में अनुसूचित जाति समाज के विकास हेतु प्राधिकरण का गठन किया गया था। वर्तमान सरकार ने उसके बजट को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ कर दिया है। धर्मगुरु गुरु बालदास साहेब ने कहा कि यह मेला सामाजिक सौहार्द और एकजुटता का प्रतीक है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि कुतुब मीनार से भी ऊँचा जैतखाम छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी में है। यह किसी व्यक्ति की उपलब्धि नहीं बल्कि गुरु बाबा घासीदास की प्रेरणा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गरीबों के उत्थान और प्रदेश को आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया है, वह साकार हो रहा है। किसानों, महिलाओं, युवाओं और मजदूरों के हित में योजनाएँ बन रही हैं। मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि यह मेला गुरु घासीदास बाबा के पुत्र गुरु श्री बालकदास साहेब के गद्दीनशीन होने की स्मृति में प्रतिवर्ष आयोजित होता है। यह सतनाम धर्म के आदर्शों का प्रतीक है। आज ही के दिन गुरु बालकदास ने राजगद्दी स्वीकार कर भंडारपुरी की पावन भूमि को अपनी कर्मभूमि बनाया था। इस अवसर पर राजागुरु, धर्मगुरु गुरु बालदास साहेब, बाबा गुरु ढालदास साहेब, गुरु मक्सूदन साहेब, गुरु सोमेश बाबा, गुरु सौरभ साहेब, सांसद कमलेश जांगड़े, सीएसआईडीसी के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष केदार गुप्ता, जिला पंचायत रायपुर के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, विधायक श्री डोमन लाल कोर्सेवाड़ा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, श्रीमती मोना सेन, अमित चिमनानी, श्याम नारंग, नवीन मार्कण्डेय सहित समाज के संतजन एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

पेरिस जलवायु समझौता हुआ नाकाम

जीवाश्म ईंधन के उत्पादन को कई देश दे रहे हैं बढ़ावा

जलवायु परिवर्तन की एक नई रपट ने चेतावनी दी है कि पेरिस जलवायु समझौते के दस साल बाद भी कई देश जीवाश्म ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। उत्पादन अंतराल रपट 2025 के अनुसार, अनेक देशों की सरकारें 2030 तक कोयला, तेल और गैस के उत्पादन की योजना बना रही हैं, जो वायुमंडल की तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए जरूरी ईंधन से दोगुने से अधिक हो सकता है। यह उत्पादन लक्ष्य से 120 प्रतिशत अधिक और 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के लक्ष्य से 77 प्रतिशत अधिक है। पेरिस समझौता 2025 में 10 साल पूरे कर रहा है। इसके अंतर्गत देशों ने तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित रखने और इसे दो डिग्री से बहुत नीचे रखने के प्रयास की प्रतिबद्धता जताई थी। दुबई में आयोजित हुए सीओपी 28 में सरकारों ने 'ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से दूसरे स्रोतों की ओर जाने' के आह्वान पर सहमति व्यक्त की थी। स्टाकहोम एनवायरमेंट इंस्टीट्यूट (एसईआई) और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट एनालिटिक्स (यूएनईपी) की रपट के अनुसार जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करने की बजाए सरकारें अब सामूहिक रूप से 2035 तक कोयला उत्पादन, 2050 तक गैस उत्पादन और सदी के मध्य तक तेल उत्पादन में निरंतर वृद्धि की योजना बना रही हैं। अतएव कहा जा सकता है कि व्यतीत हो चुके समय की भरपाई के लिए आने वाले दशकों में जीवाश्म ईंधन उत्पादन में और भी तेजी से कमी लानी होगी।

भारत, अमेरिका, चीन, रूस, सऊदी अरब और आस्ट्रेलिया सहित 20 प्रमुख उत्पादकों को शामिल करते हुए किए गए विश्लेशण से पता चला है कि 17 देश अभी भी 2030 तक एक जीवाश्म ईंधन का उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। अर्थात कोयला, तेल या गैस का उत्पादन दो साल पहले की तुलना में कहीं अधिक होगा। रपट में बताया है कि 2030 तक कोयला उत्पादन 1.5 डिग्री सेल्सियस के अनुरूप स्तर से 500 प्रतिशत अधिक होगा, तेल 31 और गैस का उत्पादन 92 प्रतिशत से अधिक होगा। जबकि वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2040 तक कोयले का उपयोग लगभग समाप्त करने और 2050 तक तेल एवं गैस उत्पादन में तीन चौथाई कटौती की प्रतिबद्धता जताई थी।

धरती पर रहने वाले जीव-जगत पर करीब तीन दशक से जलवायु परिवर्तन के वर्तमान और भविष्य में होने वाले संकटों की तलवार लटकी हुई है। मनुष्य और जलवायु बदलाव के बीच की दूरी निरंतर कम हो रही है। पर्यावरण विज्ञानियों ने बहुत पहले जान लिया था कि औद्योगिक विकास से उत्सर्जित कार्बन और षहरी विकास से घटते जंगल से वायुमंडल का तपमान बढ़ रहा है, जो पृथ्वी के लिए घातक है। इस सदी के अंत तक पृथ्वी की गर्मी 2.7 प्रतिशत बढ़ जाएगी, नतीजतन पृथ्वीवासियों को भारी तबाही का सामना करना पड़ेगा। इस मानव निर्मित वैश्विक आपदा से निपटने के लिए प्रतिवर्श एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जिसे कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी/कॉप) के नाम से भी जाना जाता है की पिछली बैठक सीओपी 28वीं दुबई में संपन्न हुई थी। पेरिस समझौते के तहत वायुमंडल का तापमान औसतन 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने के प्रयास के प्रति भागीदार देशों ने वचनबद्धता जताई थी। लेकिन वास्तव में अभी तक 56 देशों ने संयुक्त राश्ट्र के मानदंडों के अनुसार पर्यावरण सुधार की घोषणा की है। इनमें यूरोपीय संघ, अमेरिका, चीन जापान और भारत भी शामिल हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन तथा इजरायल और फिलिस्तीन युद्ध के चलते कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण और नवीकरणीय ऊर्जा को जो बढ़ावा दिया जाना था, वह उम्मीद के अनुरूप नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जिन देशों ने वचनबद्धता निभाते हुए कोयला से ऊर्जा उत्सर्जन के जो संयंत्र बंद कर दिए थे, उन्हें रूस द्वारा गैस देना बंद कर दिए जाने के बाद फिर से चालू करने की तैयारियां हो रही हैं। ब्रिटेन में हुई पहली औद्योगिक क्रांति में कोयले का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1500 ईसवीं में बड़ी मात्रा में कोयले के उत्खनन की षुरूआत हुई थी। इसके बाद जिन देशों में भी कारखाने लगे, उनमें लकड़ी और कोयले का प्रयोग लंबे समय तक होता रहा। दुनिया की रेलें भी कोयले से ही लंबे समय तक चलती रही हैं। भोजन पकाने, ठंड से बचने और उजाले के उपाय भी लकड़ी जलाकर किए जाते रहे हैं। अतएव धुएं के बड़ी मात्रा में उत्सर्जन और धरती के तापमान में वृद्धि की षुरुआत औद्योगिक क्रांति की बुनियाद रखने के साथ ही आरंभ हो गई थी। इसके बाद जब इन दुश्प्रभावों का अनुभव पर्यावरणविदों ने किया तो 14 जून 1992 में रियो डी जनेरियो में पहला अंतरराश्ट्रीय पृथ्वी संयुक्त राश्ट्र सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप जापान के क्योटो षहर में 16 फरवरी 2005 को पृथ्वी के बढ़ते तापमान के जरिए जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल अंतराष्ट्रीय संधि अस्तित्व में आई। इस संधि में शामिल देशों ने ग्रीन हाउस अर्थात मानव उत्सर्जित गैसों को कम करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। दुनिया के वैज्ञानियों ने एक राय होकर कहा कि मानव निर्मित गैस सीओ-2 के उत्सर्जन से धरती का तापमान बढ़ रहा है, जो जीवाश्म ईंधन का पर्याय है। 192 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हुए हैं।

लेकिन वर्तमान में चल रहे दो भीषण युद्ध ने हालात बदल दिए हैं। नवंबर 2021 में ग्लासगो में हुए वैश्विक सम्मेलन में तय हुआ था कि 2030 तक विकसित देश और 2040 तक विकासशील देश ऊर्जा उत्पादन में कोयले का प्रयोग बंद कर देंगे। यानी 2040 के बाद थर्मल पावर अर्थात ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले से बिजली का उत्पादन पूरी तरह बंद हो जाएगा। तब भारत-चीन ने पूरी तरह कोयले पर बिजली उत्पादन पर असहमति जताई थी, लेकिन 40 देशों ने कोयले से पल्ला झाड़ लेने का भरोसा दिया था। 20 देशों ने विश्वास जताया था कि 2022 के अंत तक कोयले से बिजली बनाने वाले संयंत्रों को बंद कर दिए जाएंगे। परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन बदलते हालातों में हमें जिंदा रहना है तो जिंदगी जीने की षैली को भी बदलना होगा। हर हाल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करनी होगी। यदि तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक काल के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है तो कार्बन उत्सर्जन में 43 प्रतिशत कमी लानी होगी। आईपीसीसी ने 1850-1900 की अवधि को पूर्व औद्योगिक वर्श के रूप में रेखांकित किया हुआ है। इसे ही बढ़ते औसत वैश्विक तापमान की तुलना के आधार के रूप में लिया जाता है। गोया, कार्बन उत्सर्जन की दर नहीं घटी और तापमान में 1.5 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो असमय अकाल, सूखा, बाढ़ और जंगल में आग की घटनाओं का सामना निरंतर करते रहना पड़ेगा। बढ़ते तापमान का असर केवल धरती पर होगा, ऐसा नहीं है। समुद्र का तापमान भी इससे बढ़ेगा और कई शहरों के अस्तित्व के लिए समुद्र संकट बन जाएगा।

रावण दहन करने आये भगवान राम, लक्ष्मण, सीता को अध्यक्ष ने मंच के पीछे दिया स्थान, बजरंग दल ने किया विरोध

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। नगर की कृषि उपज मंडी में 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व पर रावण दहन करने आये रामलीला मंडल के पत्रों में भगवान राम लक्ष्मण माता सीता तथा हनुमान सहित अनेक पात्र रावण दहन करने पहुंचे तो भाजपा के नगर परिषद अध्यक्ष देवेन्द्र भारद्वाज ने भगवान राम सीता सहित अन्य को मंच पर आगे स्थान न देकर मंच पर पीछे स्थान दिया जाने के कारण बजरंग दल के जिला उपाध्यक्ष भवानी राजपूत और तहसील अध्यक्ष विकाश शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए अध्यक्ष देवेन्द्र भारद्वाज को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारे आराध्य भगवान राम सहित सभी पात्रों को मंच पर सबसे आगे स्थान नहीं दिया तो यहीं मंच पर धरना प्रदर्शन कर देंगे। इतना सुनते ही मंच पर हलचल मच गई और तत्काल सभी मंचासीनों ने रामलीला मंडल के पात्र भगवान राम, लक्ष्मण, सीता को आगे स्थान दिया तब जाकर मामला शांत हुआ।

मंडल अध्यक्ष के कहने पर नहीं पहुंचे भाजपा पदाधिकारी

भाजपा के मंडल अध्यक्ष अतुल बारंगे ने बयान जारी करते हुए समस्त भाजपा पदाधिकारियों को दशहरा पर्व पर मंच पर न जाने का आदेश जारी किया गया था। इसके बाद एक भी भाजपा का पदाधिकारी मंच पर नहीं पहुंचे संगठन के फरमान के बाद नगर परिषद के कुछ भाजपा पार्षद भी मंच पर नजर नहीं आये। सिर्फ भाजपा के नगर परिषद अध्यक्ष ही मंच बने रहे। मामला यह था कि नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा दशहरा पर्व की शुभकामनाएँ संदेश होर्डिंग बोर्ड पर देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित प्रभारी मंत्रीयों की फोटो नहीं लगाने और संगठन की अवहेलना करने पर मंडल अध्यक्ष अतुल बारंगे ने एक फरमान जारी करते हुए जिला अध्यक्ष से शिकायत भी की थी।

कब होगा "लापरवाही" का विसर्जन

त्योहारों पर हादसों के लिए कौन है जिम्मेदार

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

भारत पर्वों और उत्सवों का देश है। यहाँ हर त्योहार जीवन के उल्लास, उमंग और आस्था का प्रतीक है। लेकिन यदि ये उत्सव की लहरें मातम का सैलाब बन जाएँ तो समाज को ठहर कर सोचने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश की कुछ हालिया घटनाएँ सिर्फ आँकड़े नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी हैं। हमारे लिए सबसे जरूरी बिंदु अब यह है कि सब मिलकर यह विचार करें कि इस "लापरवाही" का विसर्जन कब होगा। खंडवा के पंधाना क्षेत्र में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए तालाब में उतरती एक ट्रैक्टर-ट्रॉली हादसे का कारण बनी। इस घटना में 11 जिंदगियाँ डूब गईं, जिनमें अधिकांश मासूम बच्चियाँ थीं, जिनकी खुशियाँ हमेशा के लिए खामोश हो गईं। उज्जैन के इंगोरिया क्षेत्र में विसर्जन के दौरान एक ट्रॉली चंबल नदी में समा गई। इस हादसे में तीन बच्चों की मृत्यु हुई। कटनी में दशहरे के दिन एक तालाब में दो सगे भाइयों (8 और 10 वर्ष) की मौत हो गई। नहाने की खुशी उनके लिए अंतिम सफर बन गई। इसी तरह बैतूल के मुलताई में भी विसर्जन के दौरान एक हादसा हुआ, जिसमें एक बच्ची तालाब में डूब गई। पिछले साल 26 सितंबर 2024 को बिहार में 'जीवित्पुत्रिका' व्रत के दौरान 15 जिलों में नदियों और तालाबों में बढ़े जल स्तर के कारण कम से कम 46 लोग डूब गए, जिनमें 37 बच्चे और 7 महिलाएँ थीं। इन घटनाओं से यह स्पष्ट है कि यह केवल अनियंत्रित दुर्घटनाएँ नहीं, बल्कि हमारी लापरवाही, प्रशासनिक अभाव और सामाजिक संवेदनशीलता की कमी का सामूहिक परिणाम हैं। ऐसी घटनाओं के बाद हर बार

मन में यही सवाल उठता था- काश! थोड़ी सी सतर्कता बरती गई होती। काश! प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी की होती। काश! समाज ने अपनी ज़िम्मेदारी समझी होती। संसाधन, इच्छाशक्ति और ज़िम्मेदारी- ये तीनों जब तक एक साथ नहीं मिलेंगे, तब तक मासूम जानें जाती रहेंगी।

कहाँ है कमी— कारणों का विश्लेषण

व्यक्तिगत और पारिवारिक चूकः त्योहार-भीड़ के बीच "कुछ नहीं होगा" की मानसिकता जानलेवा साबित होती है। बच्चों पर से एक पल की निगरानी हटना या यह मान लेना कि "सब देख रहे हैं," अक्सर त्रासदी का कारण बनता है।

सामाजिक और प्रशासनिक उदासीनताः विसर्जन स्थलों पर न्यूनतम सुरक्षा इंतजामों—बैरिकेडिंग, रोशनी, गोताखोर, एम्बुलेंस—का अभाव आम है। असुरक्षित वाहनों (जैसे ट्रैक्टर-ट्रॉली) का सवारियों के लिए उपयोग एक खतरनाक प्रथा है, जिसे रोका नहीं जाता।

जीवन-रक्षक कौशल की कमीः अधिकांश लोगों को तैरना नहीं आता और वे पानी की गहराई या धारा की तीव्रता का सही अंदाजा नहीं लगा पाते। बच्चों को जल-सुरक्षा और तैराकी का प्रशिक्षण न देना एक बड़ी चूक है।

प्राकृतिक कारण और समय-चयनः जैसा बिहार हादसे में हुआ। भारी मानसून वर्षा और बढ़े हुए जल स्तर ने खतरनाक स्थिति बनाई। ऐसे समय में जब जल स्तर स्वाभाविक रूप से ऊँचा हो, तो सुरक्षा उपायों की जरूरत कई गुना बढ़ जाती है।

प्रस्तावित समाधान- बहुस्तरीय ज़िम्मेदारी

अभिभावकों की जिम्मेदारियाँः

बच्चों को कभी भी अकेला नदी, तालाब या जलाशय के किनारे न जाने दें।

बच्चों को तैरना सिखाएँ- यह केवल एक खेल नहीं, जीवन बचाने का कौशल है।

समाज और स्थानीय संगठनः

गाँव/मोहल्ला स्तर पर "विसर्जन सुरक्षा समितियाँ" गठित हों, जो प्रशासन के साथ मिलकर सुरक्षा सुनिश्चित करें।

केवल निर्धारित और सुरक्षित घाटों का ही प्रयोग हो, ताकि भीड़ नियंत्रण आसान हो।

युवा मंडल जल-सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाएँ।

पंचायत/स्थानीय निकायः

खतरनाक तालाबों, खदानों और असुरक्षित किनारों पर स्थायी चेतावनी बोर्ड और बैरिकेडिंग हो। त्योहारों और मानसून में संवेदनशील स्थानों पर जल-सुरक्षा गार्ड या प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की तैनाती की जाए।

प्रशासन एवं पुलिसः

प्रत्येक विसर्जन स्थल पर SDRF/NDRF या स्थानीय गोताखोर दल, एम्बुलेंस और प्राथमिक चिकित्सा किट अनिवार्य हो।

जुलूसों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल और रूट पहले से तय हों और उनका सख्ती से पालन कराया जाए।

ट्रैक्टर-ट्रॉली जैसे कृषि वाहनों का सवारियों हेतु उपयोग प्रतिबंधित हो और उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई हो।

बड़े आयोजनों के लिए एक "आयोजन आयुक्त" नियुक्त हो और भीड़-प्रबंधन (Crowd-Flow Management) विशेषज्ञों की सलाह ली जाए।

जीवन की सुरक्षा ही सच्ची पूजा है

उत्सव चाहे दुर्गा पूजा हो, गणेशोत्सव, दशहरा हो या जीवित्पुत्रिका व्रत — ये शक्ति, जीवन और भक्ति के प्रतीक हैं। लेकिन यदि हमारी आस्था के प्रदर्शन में एक भी मासूम की जान जाती है, तो वह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक विफलता है।

इसलिए, संकल्प लें:

- **अभिभावक बनें प्रहरी।**
- **समाज बने संगठित।**
- **प्रशासन बने जवाबदेह।**

सबसे बड़ा विसर्जन लापरवाही का होना चाहिए। आइए, यह सुनिश्चित करें कि अगला त्योहार खुशियों की लहर लेकर आए, मातम की नहीं।

सितंबर में भी सैलाब का सितम

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

इस साल देश में बारिश का कहर लगातार जारी है और मॉनसून की वापसी में अभी देरी दिख रही है। अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है, जिसके चलते उत्तर भारत, पूर्व भारत और महाराष्ट्र-कर्नाटक-गोवा जैसे इलाकों में 25 से 29 सितंबर के बीच फिर से भारी बारिश का दौर चल सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में 23 से 27 सितंबर के दौरान कई जगहों पर आंधी-तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी है। कुछ पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में सितंबर के उत्तरार्ध तक बारिश जारी रह सकती है। मानसून की विदाई कब होगी? आमतौर पर उत्तर भारत में मॉनसून की वापसी (retreat) सितम्बर के अंत या अक्टूबर के पहले हफ्ते में शुरू होती है। इस साल बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में बन रही मौसमीय गतिविधियों के कारण मॉनसून की विदाई देरी से हो सकती है और दशहरा तक बारिश का सिलसिला बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा सहित अन्य राज्यों में बना रह सकता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश का सिलसिला सितंबर के आखिर तक टुकड़ों में चलता रहेगा, लेकिन फिर धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। अगस्त 2025 में उत्तर-पश्चिम भारत में 125 सालों में सबसे ज्यादा बारिश हुई। दिल्ली, पंजाब, बिहार सहित कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति बनी रही। पूरे देश में औसतन लगभग आठ फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। लोग बातें कर रहे कि आखिर मॉनसून कब तुम मानोगे? सामान्यतया सितंबर के मध्य में मॉनसून की वापसी शुरू होने लगती है और अक्टूबर की शुरुआत तक इसका प्रभाव खत्म हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता।

भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त 2025 में उत्तर पश्चिम राज्यों में भारी बारिश ने 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस इलाके में अगस्त में 265 मिमी वर्षा हुई है। ये 1901 के बाद यानी 125 सालों में भयंकर बरसात की 13वीं सबसे बड़ी घटना है। उत्तर पश्चिम इलाकों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, के साथ दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, चंडीगढ़ और लद्दाख आते हैं। इसमें तीन हिमालयी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर ने सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन, बादल फटने जैसी घटनाएं झेली हैं।

सितंबर 2025 में भारत के कई राज्यों में सैलाब और बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई, जिसमें उत्तर भारत, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात प्रमुख रूप से प्रभावित रहे। बाढ़ के प्रमुख कारण मौसम विभाग (IMD) ने सितंबर 2025 में सामान्य से अधिक वर्षा का पूर्वानुमान दिया था, जिससे औसत वर्षा 109% से अधिक रही। लगातार तेज और व्यापक बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ाया, विशेषकर यमुना, गंगा, सतलुज, ब्यास और रावी में। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं और पश्चिमी विक्षोभों की भूमिका, हिमालय की तलहटी में टकराव से स्थानीय स्तर पर भारी वर्षा हुई। डैम से पानी छोड़ना (जैसे भाखरा और पोंग डैम) ने निचले इलाकों में पानी भर दिया। जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून अनियमित और तीव्र हुआ, जिससे बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ीं। प्रभावित क्षेत्र और नुकसान पंजाब में 2300 गाँव और 20 लाख लोग प्रभावित हुए, 7 लाख लोग बेघर हो गए और लगभग 5 लाख एकड़ फसलें जलमग्न हो गईं। दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश के कई शहर, राजस्थान, गुजरात समेत अनेक इलाकों में जलभराव, यातायात बाधित, और जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा। हिमाचल-उत्तराखंड में बादल फटने, भूस्खलन से सैकड़ों गांव, पुल, सड़कें, और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। जानमाल की भारी क्षति, केवल पंजाब में 46 और उत्तराखंड में 13 से अधिक मौतें दर्ज की गईं। राहत के काम में चुनौतियाँ थीं। लाखों लोग राहत कैंपों में थे। उनके राशन व मेडिकल सहायता की व्यवस्था कराया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरदासपुर (पंजाब) का दौरा किया, राहत कार्यों का जायजा लिया। विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन, तटबंधों की कमजोरी, जल निकासी अतिक्रमण और अनियोजित निर्माण को बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहराया है। सितंबर में बाढ़ और सैलाब का सितम असामान्य मौसम कारणों के साथ-साथ मानवीय गलतियों और व्यवस्थागत कमजोरियों का परिणाम रहा। मौसम विभाग के सारे ताजा अपडेट्स के अनुसार, अगले कुछ दिन, विशेष तौर पर 29 सितम्बर तक बारिश का दौर जारी रहेगा, राहत मिलने की उम्मीद सितंबर के आखिरी सप्ताह या अक्टूबर की शुरुआत से है, तब जाकर बारिश का कहर धीरे-धीरे थमेगा। देश के कई हिस्सों में बारिश की समाप्ति के कोई पक्के दिन नहीं हैं।

गौरवशाली 25 वर्ष

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25

हमर छत्तीसगढ़

विकास और विश्वास का नया दौर

स्वास्थ्य

सन् 2000

- स्वास्थ्य सूचकांक: 0.585
- शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्म पर 77
- ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचा कमजोर
- जिला अस्पतालों की संख्या 06

सन् 2025

- स्वास्थ्य सूचकांक: 0.672
- शिशु मृत्यु दर: प्रति हजार जीवित जन्म पर 38
- ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण
- जिला अस्पतालों की संख्या 30

R.O. No. : 13456/ 1

सुशासन से समृद्धि की ओर

Visit us : ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)